महत्वपूर्ण
ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
चतुर्थ तल नव चेतना केन्द्र
10, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा–431– / 2018–19 / 23 लखनऊ : दिनांक 10 जनवरी, 2019

विषय : आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत एस0ई0सी0सी0 2011 डाटा में सम्मिलित अपात्र परिवारों को डाटा से हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या एन0एच0पी0एम0 / पत्रा–431– / 2018–19 / 1076 दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नेशनल हेल्थ एजेन्सी द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 30 अगस्त, 2018 को संलग्न कर प्रेषित करते हुये आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है।

भारत सरकार के उक्त सर्कुलर में प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत लाभार्थी सूची में सम्मिलित अपात्र परिवारों का नाम हटाने के लिये आवश्यक कार्यवाही का दायित्व जिलाधिकारियों को सौंपा गया है। सर्कुलर की छायाप्रति पुनः आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

दिनांक 04.01.2019 को वाराणसी में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश सरकार तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नेशनल हेल्थ एजेन्सी, भारत सरकार द्वारा पुनः इस बात पर बल दिया गया कि सर्कुलर में उल्लिखित Exclusion Criteria के आधार पर अपात्र परिवारों को चिन्हित करते हुये उनका नाम सूची से हटाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार के संलग्न सर्कुलर में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप जनपद में अपात्र परिवारों को चिन्हित करते हुये उनका विवरण प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे उनका नाम समयान्तर्गत पात्रता सूची से हटाया जा सके।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

10.1.19

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक : ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा–431– / 2018–19 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
National Health Agency

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated: 30th August, 2018

CIRCULAR

Subject: Regarding authorizing DC/DMs to implement exclusion clauses in SECC Data.

Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojaja is targeted to benefit 10.74 crore poor, deprived rural families and identified occupational category of urban workers' families as per the Socio Economic Caste Census (SECC) 2011. The SECC 2011 is a study of socio economic status of rural and urban households that allows ranking of households based on predefined parameters. It was conducted under the overall coordination of Department of Rural Development. The data is based on 2011 SECC Census riding over National Population Register demographies. As per the SECC 2011, the following beneficiaries are automatically excluded:

i. Households having motorized 2/3/4 wheeler/fishing boat.
ii. Households having mechanized 3/4 wheeler agricultural equipment
iii. Households having Kisan Credit Card with credit limit above Rs. 50,000.
iv. Household member is a Government employee.
v. Households with non-agricultural enterprises registered with Government.
vi. Any member of household earning more than 10,000 per month.
vii. Households paying income tax.
viii. Households paying professional tax.
ix. House with three or more rooms with pucca walls and roof.
x. Owns a refrigerator
xi. Owns a landline phone.
xii. Owns more than 2.5 acres of irrigated land with 1 irrigation equipment.
xiii. Owns 5 acres or more of irrigated land for two or more crop season
xiv. Owning at least 7.5 acres of land or more with at least one irrigation equipment.

2. This study was conducted in 2011, an additional data collection drive was undertaken to update family data. However, there may still be some glaring instances, where some of those who have to be automatically excluded in 2011 but are figuring in the list of eligible beneficiaries. In such cases, States re advised to authorize the District Collectors/District Magistrates or Deputy Commissioners to exclude such beneficiaries from the eligibility list. This should be done on the basis of written representation and after due summary inquiry is conducted into each particular case.

(Dr. Indu Bhushan)
Chief Executive Officer
National Health Agency

To All Chief Secretaries of States